आकाशवाणी
क्षेत्रीय समाचार
देहरादून (उत्तराखण्ड)
रविवार 23.11.2025
समय 07.20

मुख्य समाचार :–

- राज्य में वन्यजीव हमलों में घायल व्यक्यिों के उपचार का पूरा खर्च सरकार वहन करेगी।
- प्रदेश में सहकारी समितियों के चुनावों में महिला सशक्तिकरण की मजबूत उपस्थिति; राज्य की 281 समितियों की बागडोर अब महिलाओं के हाथ में।
- यूपीसीएल उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए उपखंड स्तर पर विशिष्ट विद्युत सेवा शिविर आयोजित करेगा।
- मुख्य कोषागार देहरादून में पेंशनरों के लिए 25 नवंबर को पेंशन जागरूकता एवं निःशुल्क चिकित्सा शिविर आयोजित किया जाएगा।

वन्यजीव हमले/उपचार खर्च वहन करेगी सरकार

राज्य में वन्यजीव हमलों में घायल व्यक्यिों के उपचार का पूरा खर्च सरकार वहन करेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि घायलों को समय पर और उचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने संबंधित विभागों से इलाज में देरी न होने और आवश्यक संसाधन तुरंत उपलब्ध कराने को कहा।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव वन के साथ बैठक कर राज्य में बढ़ रही वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं पर चिंता जताई। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि इलाज के साथ प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा और जागरूकता को भी मजबूत किया जाए।

गौरतलब है कि सरकार ने वन्यजीव हमलों में मृतकों के परिजनों को दिए जाने वाले मुआवजे को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया है।

महिला सशक्तीकरण

उत्तराखंड में सहकारी समितियों के चुनावों में महिला सशक्तिकरण की मजबूत उपस्थिति देखने को मिली है। प्रदेश की 668 समितियों में से 281 समितियों की बागडोर अब महिलाओं के हाथों में रहेगी, जबकि 159 समितियों में उपाध्यक्ष पद पर भी महिलाओं ने जीत दर्ज की है।

सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि सहकारी समितियों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से सहकारिता आंदोलन को नई दिशा मिलेगी और पारदर्शिता व उत्तरदायित्व जैसे मूल्यों को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने सहकारिता में 33 प्रतिशत आरक्षण का निर्णय लेते हुए महिलाओं के नेतृत्व को प्रोत्साहन दिया था, जिसके सकारात्मक परिणाम अब सामने आ रहे हैं।

डॉक्टर रावत ने बताया कि प्रदेश की 671 प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों में हुए चुनावों में 6 हजार 486 संचालकों में से 2 हजार 517 महिलाएँ निर्वाचित हुई हैं। विभिन्न जिलों में बड़ी संख्या में महिलाएँ संचालक मंडल में शामिल हुई हैं।

आह्वान

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रशासनिक अधिकारियों को पारदर्शी और जन–केंद्रित कार्यशैली अपनाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि जनता के विश्वास को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए फाइलों में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए और लक्ष्य आधारित निर्णयों पर तेजी से काम होना चाहिए।

मुख्यमंत्री अपने आवास पर आईएएस अधिकारियों की अनौपचारिक बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा बताए गए "उत्तराखंड का दशक" के संकल्प को साकार करना प्रशासन की जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले पांच वर्ष राज्य के लिए निर्णायक होंगे और प्रशासन को अधिक गति और दृढ़ता के साथ कार्य करना होगा ताकि जनता को सकारात्मक बदलाव महसूस हो।

उन्होंने कहा कि राज्य ने 25 वर्षों की यात्रा में अनेक चुनौतियों का सामना किया है और इन उपलब्धियों में प्रशासन की निष्ठा और मेहनत का बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि योजनाओं और निर्णयों का असर जमीनी स्तर पर तुरंत दिखना चाहिए और फाइलों का निस्तारण समयबद्ध तरीके से किया जाना चाहिये।

नई श्रम संहिता–मुख्यमंत्री प्रतिक्रिया

देश में चार नई श्रम संहिताओं के लागू होने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इससे देश के कार्यबल में नए युग की शुरुआत हुई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार श्रम संहिताओं के अनुपालन के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और ये सुधार, लंबे समय में सकारात्मक परिणाम देंगे।

मुख्यमंत्री ने बताया कि पहले के श्रम कानूनों में असंगठित क्षेत्र के बड़े वर्ग को सामाजिक सुरक्षा नहीं मिल पाती थी और न्यूनतम वेतन भी कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित था। पुराने कानूनों से कारोबार में सुगमता प्रभावित होती थी और विदेशी निवेश पर भी प्रतिकूल असर पड़ता था।

उन्होंने कहा कि नई श्रम संहिताएँ श्रमिकों के हितों की मजबूती से रक्षा करती हैं। न्यूनतम और समय पर वेतन, नियुक्ति पत्र की अनिवार्यता, महिला श्रमिकों को समान वेतन और रात्रि पाली में काम की स्वतंत्रता जैसे प्रावधान महत्वपूर्ण कदम हैं। निश्चित अवधि के कर्मचारियों को एक वर्ष बाद ग्रेच्युटी और श्रमिकों के लिए वार्षिक स्वास्थ्य जांच जैसी सुविधाएँ भी शामिल हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इन सुधारों से श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा और बेहतर कार्य वातावरण मिलेगा, जबकि उद्योगों को सुगम व्यापार माहौल का लाभ होगा। राज्य के श्रमिक और उद्योग दोनों इससे लाभान्वित होंगे।

विद्युत सेवा शिविर

उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड–यूपीसीएल उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए उपखंड स्तर पर विशिष्ट विद्युत सेवा शिविर आयोजित कर रहा है। इन शिविरों का उद्देश्य उपभोक्ताओं को एक ही स्थान पर सरल और पारदर्शी विद्युत सेवाएँ उपलब्ध कराना है।

यूपीसीएल के प्रबंध निदेशक अनिल कुमार ने बताया कि शिविरों में उपभोक्ताओं की विद्युत संबंधी समस्याओं का त्वरित समाधान किया जाएगा। सभी अधिकारियों को शिविरों में उपस्थित रहकर प्रभावी संचालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। शिविरों की तिथियाँ और स्थान स्थानीय माध्यमों से उपभोक्ताओं को बताए जाएँगे।

शिविरों में नए विद्युत संयोजन से संबंधित मार्गदर्शन, मीटरिंग और बिलिंग से जुड़ी शिकायतों का निस्तारण, खराब मीटरों का बदलना, मीटर टेस्टिंग, लोड वृद्धि या कमी के आवेदन, तकनीकी समस्याओं का निरीक्षण और निराकरण किया जाएगा। स्मार्ट मीटर से जुड़ी जानकारी भी उपलब्ध कराई जाएगी।

इसके साथ ही सौर ऊर्जा योजनाओं, रूफटॉप सोलर और सब्सिडी प्रक्रिया, डिजिटल भुगतान, ऑनलाइन सेवाओं और ऊर्जा संरक्षण से संबंधित जागरूकता दी जाएगी। वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग उपभोक्ताओं के लिए विशेष सहायता डेस्क भी रखा जाएगा।

पेंशन जागरुकता और चिकित्सा शिविर

मुख्य कोषागार देहरादून में पेंशनरों के लिए 25 नवंबर को पेंशन जागरूकता शिविर और निःशुल्क चिकित्सा शिविर आयोजित किया जाएगा। यह शिविर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगा।

शिविर में पेंशनरों का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा और डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट, साइबर सुरक्षा, आयकर अधिनियम और चिकित्सा प्रतिपूर्ति से जुड़े विषयों की जानकारी दी जाएगी। डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए मोबाइल ऐप, कोषागार में बायोमैट्रिक उपकरण, पोस्टमैन और जन सुविधा केंद्र सहित सभी विकल्प उपलब्ध हैं।

कोषागार देहरादून से लगभग 21 हजार पेंशनर पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। पेंशनरों को डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के लिए प्रोत्साहित करने और इसकी प्रक्रिया समझाने के लिए प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।

मुख्य कोषाधिकारी ने सभी पेंशनरों से शिविर में अधिक संख्या में शामिल होने की अपील की है।

रैम प्रहार

भारतीय सेना की खड्ग कोर के तहत रैम डिविजन ने हरिद्वार में सैन्य अभ्यास 'रैम प्रहार' का सफल आयोजन किया। अभ्यास के समापन पर पश्चिमी कमांड के जीओसी–इन–सी लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार ने इसका निरीक्षण किया।

यह संयुक्त सैन्य अभ्यास आधुनिक और तकनीक–सक्षम सेना की क्षमताओं को परखने के उद्देश्य से किया गया था। अभ्यास के दौरान सेना ने भूमि, वायु और साइबर सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपनी परिचालनिक तेजी और वास्तविक समय में निर्णय लेने की क्षमता का प्रदर्शन किया।

अभ्यास से पहले रैम डिविजन ने विभिन्न युद्धाभ्यास ड्रिल और कार्यनीति का सत्यापन किया। अभियान के दौरान बख्तरबंद सेना, पैदल सेना, इंजीनियर और आर्मी एविएशन ने समन्वित रूप से भाग लिया। अत्याधुनिक उपकरणों, आई.एस.आर प्रणाली, ए.आई आधारित निर्णय सहायता तंत्र और नेटवर्क–सक्षम कमांड एवं कंट्रोल प्रणाली का भी उपयोग किया गया।

स्वच्छता अभियान

धर्मनगरी हरिद्वार को स्वच्छ और सुंदर जिला बनाने के लिए चल रहा सफाई अभियान कल चौथे दिन भी जारी रहा। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने सभी अधिकारियों को अपने–अपने क्षेत्रों में उतरकर सफाई व्यवस्था की निगरानी करने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों और राष्ट्रीय राजमार्ग तक सफाई कार्य किया गया।

नगर पालिका मंगलौर क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग की सर्विस लाइन पर सफाई अभियान चलाया गया। भगवानपुर क्षेत्र की ग्राम पंचायत सिसोना, मज़ाहिदपुर सत्तीवाला, बेसरी मार्केट और लक्सर–रुड़की रोड सहित कई स्थानों पर भी साफ–सफाई की गई।

ज़िले में चल रहे अभियान का असर साफ दिख रहा है। शहरी क्षेत्रों से लेकर गांवों तक अधिकारी स्वयं मौके पर पहुंचकर सफाई कार्यों की निगरानी कर रहे हैं।

मुलाकात

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से सिडकुल इंटरप्रेन्योर वेलफेयर सोसाइटी पंतनगर के प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल ने राज्य में औद्योगिक माहौल सुधारने के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार अनुकूल नीतियां लागू कर रही है। उन्होंने बताया कि किच्छा खुरपिया पार्क, अमृतसर–कोलकाता औद्योगिक गलियारा और पंतनगर में प्रस्तावित अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट क्षेत्र के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। खुरपिया क्षेत्र में बनने वाली इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी से बड़े निवेश और रोजगार के नए अवसर मिलेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्योगों की सुविधाओं के लिए जिलाधिकारियों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। राज्य सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ कतई न बर्दाश्त करने की नीति पर काम कर रही है और उद्योगों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने कहा कि कई बड़े उद्योग राज्य में निवेश की इच्छा जता रहे हैं।